BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

भारतीय राजनीति में जाति

वर्त्तमान समय में भी भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था देखने को मिल रहा है। भारत के सभी राजनीतिक दल जातिवाद को अन्तःक्रिया के रूप में शामिल किये हुए हैं। भारतीय राजनीति में जाति पर अध्ययन करने के पूर्व जाति का परम्परागत अर्थ एवं रूपों का अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

जाति का परम्परागत अर्थ एवं रूप :– जाति प्रथा समाज के हर कोने में विद्यमान है। समाज का कोई भी वर्ग जाति प्रथा से अछूता नहीं है। यह परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में पेशे के आधार पर समाज कई वर्गो में बॅटा हुआ था। सामान्यतया यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। इस काल में ब्राहमण धार्मिक और वैदिक कार्यो का सम्पादन करते थे। क्षत्रिय देश की रक्षा तथा शासन प्रबन्ध का कार्य करते थे। वैश्य कृषि और वाणिज्य का कार्य सम्भालते थे तथा शुद्रों को उल्लेखित तीनों वर्णो की चाकरी करनी पड़ती थी। शुरू–शुरू में जाति प्रथा के बन्धन कठोर नहीं थे और न ही जन्म पर आधारित थे अपितु वे कर्म पर आधारित थे। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आती गई और वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गयी तथा एक जाति से दूसरी जाति में अन्तःक्रिया असम्भव हो गयी। श्रम का विभाजन जाति के आधार पर होने लगा। जिसके कारण एक जाति का पेशा उसी जाति में होता था। बेटा बाप से अपना पुशतैनी पेशा सीखता था और उसी को अपना आजीविका का साधन समझता था। इस प्रथा ने एक जाति और बिरादरी के लोगों ने भाईचारा की भावना को जागृत किया जिसके कारण जाति के लोग एक–दूसरे को भॅली–भॉति समझने लगे तथा उसके सुख–दुख में अपना हाथ बॅटाने लगे।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका – जाति–व्यवस्था भारतीय समाज का परम्परागत पक्ष है। आजादी के बाद संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे–धीरे प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया। इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि, "जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है।" मॉरिस जोन्स के अनुसार, "जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है।" जाति की भूमिका भारतीय राजनीति में काफी अधिक हो गई है। अतएव भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है।

1. **निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका** – भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षित वर्ग की सभी जातियॉ आपस में एकत्रित एवं संगठित होकर सरकार के स्तर पर निर्णय लेने के लिए दबाब डालती है, जिसके कारण राजनीतिक स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। सरकार के स्तर पर अधिकांश निर्णय जातिगत भावना से ग्रसित होकर लिये जाते हैं एवं प्रशासनिक स्तर पर कार्यो का बॅटवारा भी जातिगत भावना से ग्रसित होकर किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यो का निष्पादन भी जातिवादी भावना के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार निर्णय की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर जाति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. **राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय** – भारत के सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारो का चयन जातिगत आधार पर ही करते हैं। प्रत्येक राजनीति दल अपने संगठन का विस्तार भी जाति की भावना से ग्रसित होकर ही करता है उसका मुख्य द्येय होता है कि अधिक से अधिक अपनी ही जाति के लोगों को संगठन में शामिल करे। राजनीतिक दलों द्वारा जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें जाति का विशेष महत्व दिया जाता है। चुनाव के पूर्व प्रत्याशियों के चयन में सर्वप्रथम जाति का विशेष ख्याल रखा जाता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की बहुलता होती है उस क्षेत्र से उसी जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है। अर्थात् राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन का निर्णय भी जाति के आधार पर ही लेते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न चुनावों में देखने को मिलता है। जिस राजनीतिक दल में जिस

जाति की बहुलता होती है उस राजनीतिक दल में उसी जाति का वर्चस्व होता है। जैसे – राजद में यादवों का, लोक जनशक्ति पार्टी में पासवानों का इत्यादि।

3. **जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार** – भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया गया है। चुनाव के समय में सर्वप्रथम लोग अपनी ही जाति के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं तथा अपने सगे–संबंधियों, परिचितों एवं मित्रों को अपने जाति के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने जाति के प्रत्याशी को चुनाव में विजयी कराने के लिए उनके तरफ से जनता को कई तरह के प्रलोभन भी दिये जाते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव अपने जाति के नेता के रूप में तथा रामविलास पासवान भी अपने जाति के नेता के रूप में ज्यादा विख्यात हैं। चुनाव के समय अपने जाति का अधिकांश वोट जातिगत आधार पर ही प्राप्त कर लेते हैं।
4. **नियुक्यिों में जातिवाद** – भारतीय राजनीति में विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली नियुक्तियों में भी जातिवादी भावना देखने को मिलता है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन, विभिन्न बोर्डो में सदस्यों की नियुक्तियॉ भी जाति की भावना से ग्रसित होकर किया जाता है। राजद के शासन काल में अधिकांश आयोगों, बोर्डो एवं निगमों में यादवों की ही नियुक्ति की जाती थी। रामविलास पासवान के द्वारा भी ऐसा ही किया गया।
5. **मंत्रिमण्डल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व** – सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की क्यों न हो, प्रत्येक राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के बाद मंत्रिमण्डल का निर्माण जातियता के आधार पर अथवा जातिगत भावना के आधार पर ही किया जाता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा सर्वप्रथम मंत्रिमण्डल का निर्माण करते समय अपने ही जाति के लोगों को अधिक से अधिक मंत्रिमण्डल का मुख्य पद देने का काम करते हैं। अपनी जाति के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं मिलने पर ही अन्य जातियों अथवा अन्य वर्गो के निर्वाचित प्रतिनिधि को मंत्रिमण्डल में शामिल किया जाता है। कभी–कभी जनता के दिखावे के लिए भी अन्य जाति के लोगों को शामिल किया जाता है।
6. **जाति एवं प्रशासन** –लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। केन्द्र एवं राज्यों की सरकारी नौकरियों एवं पदोन्नितयों के लिए

जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी आरक्षण का प्रावधान है। 8 सितम्बर 1993 से केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ों वर्गो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। भारत के स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधान और प्रतिष्ठित अथवा संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित होते हैं।

7. **जातिगत दबाब समूह** – प्रो0 जे.सी.जौहरी के अनंसार, "जातिगत दबाब समूह अपने निहित स्वार्थो एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति–निर्मताओं को जिस ढ़ग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदायों से की जा सकती है।" विभिन्न जातिगत समूह के द्वारा भी राजनेताओं पर दबाब देकर अपने जाति के हित काम नीतियों का निर्माण करवाते हैं। अनेक जातीय संगठन एवं समुदाय यथा– यादव सभा, क्षत्रिय महासभा, वैश्य महासभा, नडार जाति संघ आदि राजनीतिक मामलों मे रूचि लेने लगते हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। राजनीतिक सौदेबाजी सफल नहीं होने पर प्रदर्शन, धरना इत्यादि का भी सहारा लेते हैं।